



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54134

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 6136 वर्ष 2026

श्रीमती सोनम बी और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहम्मद जावेद अख्तर

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार सिंह की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने हेतु परमादेश रिट जारी करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

3. दिनांक 16.02.2026 के पूर्व आदेश के अनुसार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्रस्तुत किए हैं जिन्हें रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इन निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि कृष्णा लॉज, उच्च न्यायालय, प्रयागराज में निकाह संपन्न कराने के लिए कोई संस्था स्थित नहीं है। हालांकि, यह निवेदन किया गया है कि जांच अधिकारी ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की कि दोनों पक्षों के बीच निकाह संपन्न हुआ था या नहीं। उन्होंने गवाहों और काज़ी के बयान भी दर्ज नहीं किए। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं के विवाह के संबंध में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई थी।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 9.8.2025 को रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न किया है। उन्होंने आगे बताया कि यह याचिकाकर्ताओं का पहला विवाह है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उनका विवाह उनकी स्वतंत्र सहमति से संपन्न हुआ है बिना किसी दबाव के। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं को इस विवाह के कारण प्रतिवादियों द्वारा धमकाया और परेशान किया जा रहा है।

5. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 सीआर.एल.जे. 3309** में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के एक मामले से निपटते हुए, माननीय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:

“यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे अपने बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा को उकसा नहीं सकते, और ऐसे अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। अतः हम निर्देश देते हैं कि देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई बालक या बालिका जो बालिग है, किसी बालिग स्त्री या पुरुष से अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए और न ही उन्हें धमकियों या हिंसा का शिकार बनाया जाए, और जो कोई भी ऐसी धमकियाँ देता है या परेशान करता है या हिंसा करता है, स्वयं या उसके उकसावे पर, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून द्वारा निर्धारित कठोर कार्रवाई की जाए।”

6. भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 में माननीयसर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 28 और 29 में निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“28. अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को मनमानी अदालतों के प्रकोप से बचने के लिए पुलिस लाइन या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। लता सिंह मामले में हमने यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माना है कि "इज्जत" के नाम पर हत्या में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है। ये कट्टर और सामंती मानसिकता वाले लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में, चाहे किसी भी कारण से की गई हो, इज्जत के नाम पर हत्याएं दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को जड़ से खत्म किया जाए, जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के घृणित, असभ्य व्यवहार को रोकने के लिए यह आवश्यक है। जो भी व्यक्ति "इज्जत" के नाम पर हत्या करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।

29. इस निर्णय की एक प्रति सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार को भेजी जाए, जो इसे सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों को वितरित करेंगे। उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार इसकी प्रतियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सत्र न्यायाधीशों/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को भी वितरित करेंगे। निर्णय की प्रतियां देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएंगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एसएसपी/एसपी को सूचना के लिए वितरित करेंगे।”

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं की मात्र आशंका है कि निजी प्रतिवादी हिंसा का कोई कृत्य कर सकते हैं और/या याचिकाकर्ताओं को परेशान कर सकते हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन मामले की खूबियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता विवाहित जोड़े के रूप में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित न किया जाए, यदि उसने याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है।

9. याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया जाता है कि 9.8.2025 को हुई शादी आज से दो महीने के भीतर उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत कराई जाए और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर शादी पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं तो यहाँ दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

10. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या याचिकाकर्ताओं की सही आयु पर कोई निर्णय नहीं दिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. चूंकि याचिका का प्रारंभिक चरण में ही निस्तारण किया जा रहा है, इसलिए इससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति, यदि आदेश तथ्यों को छुपाकर या गलत बयानों के आधार पर प्राप्त किया गया है, तो उसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।
12. हालांकि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच में बाधा नहीं बनेगा।
13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

18 मार्च, 2026

ए.पी. पैन

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।